

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1095

दिनांक 13.12.2022/ 22 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए
एफसीआरए के अंतर्गत लाइसेंसों को रद्द करना

1095. प्रो. सौगत राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द किए गए हैं और एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसे किसी लाइसेंस धारक/गैर-सरकारी संगठन का किसी आतंकवादी समूह से संबंध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने के कारण देश में मानवीय सहायता हेतु निधि की कमी हो गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): पिछले तीन वर्षों यानी 2019 से 2021 के दौरान, 1,811 संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण एफसीआरए, 2010 की धारा 14 के तहत रद्द कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, उनकी राज्य-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): जब भी विदेशी अभिदाय का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए किये जाने से सम्बंधित कोई जानकारी इस मंत्रालय को प्राप्त होती है, तो एफसीआरए, 2010 और अन्य मौजूदा कानूनों एवं नियमों के तहत यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(घ): नहीं, महोदय।

(ड): प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुलग्नक**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1095 दिनांक 13.12.2022**

“एफसीआरए के अंतर्गत लाइसेंसों को रद्द करना” के बारे में दिनांक 13.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1095 के संबंध में अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसोसिएशनों की संख्या जिनका पंजीकरण रद्द किया (2019 से 2021)
1	आंध्र प्रदेश	168
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	23
4	बिहार	122
5	चंडीगढ़	4
6	छत्तीसगढ़	14
7	दिल्ली	68
8	गोवा	4
9	गुजरात	45
10	हरियाणा	8
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	9
13	झारखंड	43
14	कर्नाटक	96
15	केरल	52
16	मध्य प्रदेश	54
17	महाराष्ट्र	206
18	मणिपुर	43
19	मेघालय	7
20	मिजोरम	2
21	नागालैंड	14
22	ओडिशा	109
23	पुदुचेरी	8
24	पंजाब	8
25	राजस्थान	41
26	सिक्किम	3
27	तमिलनाडु	218
28	तेलंगाना	90
29	त्रिपुरा	3
30	उत्तर प्रदेश	115
31	उत्तराखंड	31
32	पश्चिम बंगाल	193
	कुल	1,811
